राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित 20 केंद्रीय मंत्रियों को निमंत्रण

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (यूपीजीआइएस) के भव्य आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी राज्य सरकार ने उद्घाटन सत्र से लेकर समापन सत्र का खाका बुन लिया है। जीआइएस में देश और दुनिया भर के दिग्गज निवेशक तो जुटेंगे ही, साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समेत 20 से ज्यादा केंद्रीय मंत्रियों को आयोजन का हिस्सा बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री उद्घाटन समारोह में शामिल हो सकते हैं, जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को समापन समारोह का मुख्य अतिथि बनाने की तैयारी है। इसके अलावा प्रदेश सरकार की ओर से गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत 20 केंद्रीय मंत्रियों को भी

द्रौपदी मुर्मु

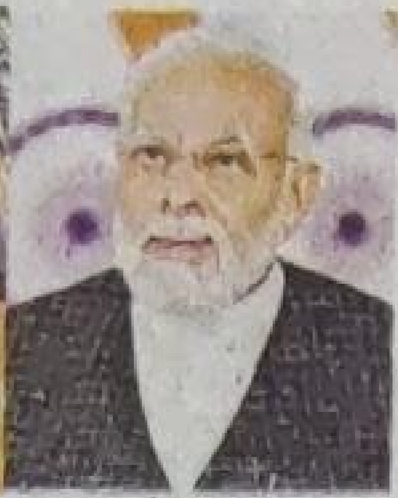

नरेन्द्र मोदी

निमंत्रण भेजा जा रहा है। देश और विदेश से आने वाले मेहमानों की सूची भी तैयार की जा रही है।

उद्घाटन और समापन सत्र के मुख्य कार्यक्रम के अलावा प्रतिदिन अलग-अलग विषय और कंट्री पार्टनर के साथ करीब आठ सत्रों का आयोजन किया जाएगा। दिन के अंत में सांस्कृतिक समारोह का आयोजन होगा। पहले दिन भारत सरकार में इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित अन्य मंत्री अलग-अलग सत्र में भाग ले सकते हैं। 11 फरवरी को दूसरे दिन कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल, आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और आइटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर के शामिल होने के आसार हैं। गृहमंत्री अमित शाह दूसरें दिन के समारोह के मुख्य अतिथि हो सकते हैं। तीसरे व अंतिम दिन केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और सोम प्रकाश उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, आवासन और शहरी कार्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी और राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह को भी आमंत्रित किया गया है। अंतिम दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विशेष सत्र को संबोधित कर सकती हैं।

पार्टनर कंट्री के लिए होंगे अलग-अलग सत्र

यूपीजीआइएस में बतौर पार्टनर कंट्री जुड़ने वाले देशों के लिए भी अलग-अलग सत्र का आयोजन होगा। सिंगापुर और नीदरलैंड्स के लिए पहले दिन का सत्र तय किया गया है। डेनमार्क और जापान के सत्र दूसरे दिन होंगे। यूके और मारीशस का सेशन तीसरे दिन होगा। इन देशों के प्रतिनिधि सत्र में अपने विचार रखेंगे।